

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-8  
संख्या 515/2017/9(120)/XXVII(8)/2017  
देहरादून:: दिनांक:: 29 जून, 2017

**अधिसूचना**

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के क्रम में ऐसे माल की पूर्ति को विनिर्दिष्ट करने की राहर्ष रवीकृति प्रदान करते हैं जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, के अन्तर्गत आती है और जिसकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है तथा जिसकी बाबत राज्य कर स्तम्भ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे माल की राज्य के भीतर पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदत्त किया जाएगा और उक्त अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे, अर्थात् :

**सारणी**

क्रम सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण	माल का पूर्तिकार	पूर्ति का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801	काजू जिनका छिलका नहीं निकाला गया है या जिन्हें छिला नहीं गया है	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
2.	1404 90 10	बीड़ी लपेटने वाले पत्ते (तेन्दू)	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
3.	2401	तंबाकू के पत्ते	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
4.	5004 से 5006	रेशम सूत	कोई व्यक्ति, जो रेशम सूत की पूर्ति के लिए कच्चे रेशम या रेशम कीट कोया से रेशम सूत का विनिर्माण करता है	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
5.	-	लाटरी की पूर्ति	राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र पशासन या कोई	लाटरी वितरक या उसका विक्रय करने वाला

			स्थानीय प्राधिकारी	<p>अभिक्ती ।  स्पष्टीकरण, इस प्राधिकार के प्रयोजनों के लिए, लाटरी वितरक या इसका विक्रय करने वाला अभिक्ती का वही अर्थ है, जो कानून लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन बनाए गए लाटरी (विनियमन) विनियम, 2010 के नियम 2 के खंड (ग) में है ।</p>
--	--	--	--------------------	--

**स्पष्टीकरण -**

- (1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविविधित क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।
  - (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए विनियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

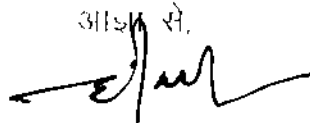
(राधा प्रसूजी)  
प्रमुख सचिव

सं० 51/5/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तदुदिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें ।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें ।
- 3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय ।
- 4- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन ।
- 5- एन0आई0सी0
- 6- गार्ड फाईल हेतु ।

*(Handwritten mark)*

आज्ञा से,  
  
(हीरा सिंह बरोडा)  
अनसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 515/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 for general information

**Government of Uttarakhand**  
**Finance Section-8**  
**No. 515/2017/9(120)/XXVII(8)/2017**  
**Dehradun :: Dated :: 29 June, 2017**  
**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor in continuation of the recommendations of the Council is pleased to allow to specify the supply of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, made by the person as specified in the corresponding entry in column (4), in respect of which the State tax shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the intra-state supply of such goods as specified in the corresponding entry in column (5) and all the provisions of the said Act shall apply to such recipient, namely:-

**TABLE**

<b>S. No.</b>	<b>Tariff item, sub-heading, heading or Chapter</b>	<b>Description of supply of Goods</b>	<b>Supplier of goods</b>	<b>Recipient of supply</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	0801	Cashew nuts, not shelled or peeled	Agriculturist	Any registered person
2.	1404 90 10	Bidi wrapper leaves (tendu)	Agriculturist	Any registered person
3.	2401	Tobacco leaves	Agriculturist	Any registered person
4.	5004 to 5006	Silk yarn	Any person who manufactures silk yarn from raw silk or silk worm cocoons for supply of silk yarn	Any registered person
5.	-	Supply of lottery.	State Government	Lottery distributor or selling agent.

			Union Territory or any local authority	<p><i>Explanation.</i> For the purpose of this entry, lottery distributor or selling agent has the same meaning as assigned to it in clause (c) of Rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010, made under the provisions of sub-section 1 of section 11 of the Lotteries (Regulations) Act, 1998 (17 of 1998).</p>
--	--	--	--	--

**Explanation. –**

(1) In this Table, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading or chapter, as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

  
 (Radha Kaur)  
 Principal Secretary